18 अक्टूबर, 2008 को 10.00 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऐलुमिनी (भूतपूर्व छात्र-वृंद) के विश्व शिखर सम्मेलन के उद्‌घाटन के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी का अभिभाषण

यह मेरे लिए घर जैसा ही है और इसीलिए समारोह की कोई जरूरत नहीं है। तथापि, आज एक विशेष अवसर है और मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं विश्वविद्यालय का आभारी हूं।

आपके सामने खड़े होकर एक सवाल भी ज़हन में उठा है: क्या कहूं और क्योंकर कहूं ?

इस बज़्म में वो कहते हैं हमें, मौके के माफ़िक बात करो।
और हमने ये दिल में ठानी है, या दिल की कहें या कुछ ना कहें।

कल अलीगढ़ विश्‍वविद्यालय के छात्रों ने विश्व भर में सर सैयद दिवस मनाया था और शाम में थोड़ी सी मात्रा में या उससे ज्यादा मात्रा में बिरयानी तथा शाही टुकड़ा बड़े चाव से खाया। यह मौका इस महान संस्था के संस्थापक की याद में उन्हें सम्मान देने का था। इस रीति को व्यवहार में लाने की जिद वास्तव में क़ाबिल-ए-तारीफ़ है।

जहां जाएं वहां तेरा फ़साना छेड़ देते हैं,
कोई महफ़िल हो तेरा रंग-ए- महफ़िल याद आता है।

हाल के दशकों में मिली सफलताओं की अनेक कहानियां आज हमारे सामने हैं। इसी वज़ह से और सर सैयद दिवस के इस मौके पर सैयद अहमद खान के संदेश को फिर से याद करने तथा अपने भीतर झांक कर देखने का अवसर है।

यह संस्था एक विशिष्ट आवश्यकता और एक दृष्टिकोण के आधार पर 1875 में वजूद में आयी। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के लाभ को

भारत के मुसलमानों तक पहुंचाना था। इसमें विवेकपूर्ण सोच और वैज्ञानिक जिज्ञासा की भावना को उनके मन में बैठाना था। अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में इस ज़रूरत के बारे में कहा है-

इस दौर में तालीम है अमराज़े-मिल्लत की दवा
है खून-ए-फ़सीद के लिए तालीम मिस्ल-ए-नश्तर

यह मिशन एक हद तक सफल हुआ किंतु उससे आगे नहीं जा पाया। इस असफलता के परिणाम स्पष्ट हैं और उनका खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है।

दो सवाल पैदा होते हैं: ऐसा क्यों हुआ? इसे कैसे सुधारा जा सकता है?

हमें इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हमारी असफलता अवधारणात्मक और व्यावहारिक थी। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सके कि शैक्षिक उन्नति एक खास तबके के लिए नहीं हो सकती और न ही इसे सामाजिक परिवर्तनों से अलग किसी शून्य में अथवा हमारे चारों ओर विद्यमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्व की उभरती जरूरतों के प्रति सजगता/चेतना के स्तरों में परिवर्तनों के बिना हासिल किया जा सकता है।

मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि-

- हम कुछ खास चीजों में ही खुश होते गए, और हमने प्राथमिक शिक्षा से सभी के लिए शिक्षा के वास्तविक मूल्य और इसकी अहमियत को नहीं समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि निरक्षरता का स्तर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर बना रहा और अभी हाल तक संपन्न वर्गों को ही आधुनिक और उच्च शिक्षा हासिल थी।
- महिला साक्षरता की जरूरत और नई पीढ़ियों के शिक्षण में उसकी प्रासंगिकता को समझ पाने में बहुत अधिक देरी हुई।

- हालांकि हमारी हालत के बारे में शिकवा जायज़ था, लेकिन यह उस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि हम स्वायत्त रूप से कार्य करने में नाकाबिल रह जाएं। हम अन्य समुदायों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों की सहायता के बिना की गई सृजनात्मक उद्यमों की पहल को देख पाने, उनके साथ बराबरी करने और अपने अनुकूल बना पाने में विफल रहे।
- सख़ावत के पारंपरिक मूल्य का अनुपालन करते हुए भी हम (कुछ अपवादों को छोड़कर) लोक प्रयोजनों के लिए संगठित लोकोपकार की जरूरत को समझ नहीं सके।

यह सब उस दौर में हुआ जब आधुनिक भारत में बदलावों का दौर नई गति पकड़ रहा था। इस जोशीले उद्यम में शामिल होने के लिए प्रासंगिक शिक्षा आवश्यक हो गई।

दोस्तो,

शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। फिर भी, ज्ञानसंपन्न समाज की आवश्यकता को पूरा करना बाकी है। उच्चतर शिक्षा में हमारा सकल नामांकन अनुपात 11 प्रतिशत ही है, जो कि चीन के 22 प्रतिशत और विकसित दुनिया के 54.6 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। सरकार का प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर वर्ष 2012 तक 15 प्रतिशत और वर्ष 2017 तक 21 प्रतिशत तक किया जाए।

अब हमारे सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि जनता के सभी वर्गों को इससे समान रूप से लाभ प्राप्त हो। यह कल के विश्व के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम के आधार पर केवल सक्रिय पद्धति से हासिल किया जा सकता है।

हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इसमें भाग न लेने पर हम हाशिये पर चले जायेंगे और यह कि सामान्य योग्यता निरर्थक हो गई है।

II

प्रत्येक चुनौती एक मौका भी है। इस मोड़ पर अलीगढ़ की बिरादरी क्या कर सकती है और उसे क्या करना चाहिए? क्या वह एक उत्प्रेरक बन सकती है? यदि हां, तो हमें कौन से व्यावहारिक कदम उठाने होंगे?

सुधार को सामाजिक ढ़ांचे की नींव से ही आरम्भ करना होगा। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हम निम्नलिखित आठ कदमों द्वारा एक नये दृष्टिकोण की नींव रखें :-

- यह सुनिश्चित करें कि हमारे अपने-अपने इलाकों में प्रत्येक बच्चा वास्तव में प्राथमिक विद्यालय जाए।
- यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे, बालक और बालिकाएं आठ वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 8 के पश्चात् बच्चे या तो दसवीं कक्षा में जाएं या फिर किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में जाएं।
- विश्वविद्यालयों अथवा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों की पहचान करें और इस कार्य में उनकी सहायता करें। उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा करें। पहचान की अभिपुष्टि एक वैध प्रयास है; विशेष छूट की कामना हमें बहुत दूर तक नहीं लेकर जाएगी।
- सरकार द्वारा हाल के महीनों में घोषित छात्रवृति योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

- नई शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए औक़ाफ़ (Awkaf) से प्राप्त आमदनी का उपयोग करने के लिए जनमत तैयार करें। कुछ स्थानों में यह किया गया है और इस पद्धति को व्यापक किए जाने की आवश्यकता है।
- सख़ावत से आगे संगठित और सकेन्द्रित परोपकार तक जाने का प्रयास करें ताकि शैक्षिक क्षेत्र में मध्यम दर्जे के तथा बड़े पैमाने के प्रयासों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये जा सकें।
- राज्य से समता की मांग करें, न कि रियायतों की; और कहीं-कहीं हमारी अपनी सफलता की कहानियों सहित दूसरों की भी सफलता की कहानियों से व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करें।

  यह व्यापक योजना भूतपूर्व छात्रों की अपने प्रिय संस्थान के प्रति स्वाभाविक चिंता के संदर्भ में प्रासंगिक है।

  फिर भी, हम में से बहुत लोगों के लिए यह वह विश्वविद्यालय नहीं है जहां हमने अपनी जवानी गुज़ारी है।

हम तेजी से बदलते युग में जी रहे हैं। बीते वर्षों के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम थी, स्थान अधिक था इसलिए दबाव कम था। आज हर तरह से स्थिति खराब हो गई है। इससे कामकाज़ पर विविध प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यह चिंता का विषय बन गया है। बीते वर्षों की याद के बजाए नई सोच ही समय की जरूरत है।

सरकारी वित्तपोषण से विश्वविद्यालय के वेतन, पेंशन और अन्य सामान्य खर्चे चलते हैं। यह काफी है, लेकिन विकासात्मक प्रयोजनों जैसे- प्रयोगशालाओं को पुनर्सज्जित करने, नए पाठ्यक्रम आरंभ करने, सुविधाओं के उन्नयन और नए छात्रावास आदि के निर्माण के लिए यह राशि अपर्याप्त

है। देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पूर्व-छात्रों के सहयोग से इनमें अच्छा सुधार हुआ है और ऐसी कोई वजह नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी ऐसा ही कार्य न कर सकें।

अवसंरचना नए कार्यक्रम का एक पहलू है। इससे अधिक महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा विषयवस्तु है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 21वीं शताब्दी के एक ज्ञानवान समाज और एक वैश्वीकृत विश्व की चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। जो कुछ पढ़ाया जाता है और जिस ढंग से पढ़ाया जाता है - यह बात अप्रासंगिक हो चुकी है। पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री और अध्यापन के तौर-तरीकों को नया रूप दिया जाना एक जरूरत बन चुकी है।

साथ ही, किसी अच्छे विश्वविद्यालय की पहचान उसके विद्वानों द्वारा किए गए अनुसंधान की गुणवत्ता से होती है। ज्ञान की सीमा को बढाने के लिए, इसे सैद्धांतिक तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा।

हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जिसका उद्देश्य अध्यापन एवं अनुसंधान की क्षमता में वृद्धि करना है, में जवाबदेही, अध्यापन-निष्पादन तथा अनुसंधान कार्य से संबंधित समस्याओं की पहचान की गई है। इन मामलों में जल्दी से जल्दी सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

III

विश्वविद्यालय के दायरे में ही उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अंतिम विश्लेषण में, विश्वविद्यालय को जवाबदेह और साथ ही साथ जिम्मेदार बनना होगा; उसे सामाजिक

मांगों के अनुरूप और समाज में चिन्तन और नीति-निर्माण का मार्गदर्शन करने की इसकी भूमिका के प्रति जवाबदेह होना होगा। इन दोनों के बीच असंतुलन संस्था के लिए हानिकर और समाज के लिए नुकसानदेह होगा।

मैं कामना करता हूं कि यह सभा अपने विचार-विमर्शों में सफल हो। इसे *नशीस्तंद, गुफतंद, बर्खास्तंद* (बैठे, बातचीत की और उठ गए) से आगे बढ़ना चाहिए और इस संबंध में व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुनर्विन्यास करने में मदद करने हेतु इसके भूतपूर्व छात्र क्या कर सकते हैं। केवल तभी यह विश्वास से कहा जा सकेगा:

कुछ हो रहा है इश्क़ ओ हवस मैं भी इम्तियाज़
आया है अब मिज़ाज तेरा इम्तहां पर।